

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>नजरसानी रेफ/टी.ए./80/2005/बीकानेर धर्मवीर सिंह बनाम सरकार</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;"><b>एकल पीठ</b> <b>श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य</b></p> <p><b>उपस्थित</b></p> <p>श्री एस.पी. सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी । श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, उप-राजकीय अधिवक्ता ।</p> <p style="text-align: center;"><b>निर्णय</b></p> <p style="text-align: right;"><b>दिनांक:- 13.02.25</b></p> <p>1. प्रार्थी द्वारा यह नजरसानी प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के अन्तर्गत रेफरेंस टी.ए. संख्या 32/99 में एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-12-2004 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है।</p> <p>2. एकलपीठ के सदस्य श्री बी.एल. मीणा, के सेवानिवृत्ति हो जाने से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा योग्य अधिवक्तागण की बहस नजरसानी प्रार्थनापत्र पर सुनी गई ।</p> <p>3. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में नजरसानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा पारित आदेश में रिकार्ड पर परिलक्षित होने वाली त्रुटि रही है, जिससे पारित निर्णय पुनरावलोकन किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थी वर्षों से काश्त करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं । माननीय न्यायालय ने अपने नजरसानीग्रस्त निर्णय के द्वारा अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को इस आधार पर निरस्त किया कि कोलोनी एरिया में अप्रार्थी धर्मवीर सिंह केवल 25 बीघा सिंचित भूमि ही निशुल्क प्राप्त कर सकता था। जबकि इस बाबत् माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रेफरेन्स में प्लिडिंग्स नहीं थी तथा इस प्रकार माननीय न्यायालय ने अभिवचनों के एकदम बाहर जाकर अपनी ओर से प्रकरण बनाकर प्रथम दृष्टया गैर कानूनी व मनमाना निर्णय दिनांक 20-12-2004 पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। माननीय न्यायालय ने अपनी ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को धारा 15एए एवं 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का बनाकर मनमाना</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  नजरसानी रेफ/टी.ए./80/2005/बीकानेर धर्मवीर सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>एवं गैर कानूनी निर्णय दिनांक 20-12-2004 पारित किया है। माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सरकार ने बिना कोई जांच पड़ताल किए अस्पष्ट अभिवचनों के आधार पर अपूर्ण रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो कानूनन संधारण योग्य ही नहीं था। फिर भी ऐसे अपूर्ण रेफरेंस को नजरसानीग्रस्त निर्णय से स्वीकार किया जाना कानूनी भूल है। अतः नजरसानी प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2004 को निरस्त किया जाकर मूल रेफरेंस को खारिज किया जावे।</p> <p>4. उप-राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान उपरोक्त समस्त तथ्यों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि नजरसानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित है तथा मंडल की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि उजागर नहीं है, जिसमें नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। नजरसानी रेफरेंस को खारिज करने का निवेदन किया।</p> <p>5. हमने योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यह निर्विवाद स्थिति है कि नजरसानी प्रार्थनापत्र मात्र निम्न आधारों पर ही स्वीकार किया जा सकता है -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निर्णय अथवा आदेश पारित करने के उपरान्त नवीन और महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी जो कि पूर्व में सम्यक् तत्परता के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे, या</li> <li>2. ऐसी भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो, या</li> <li>3. अन्य किसी पर्याप्त कारण के आधार पर</li> </ol> <p>6. हस्तगत नजरसानी प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये है, उनके बाबत इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि उक्त प्रकार के आधार रेफरेंस के तो हो सकते हैं किन्तु वे नजरसानी स्वीकार करने के आधार नहीं हो सकते है। नजरसानी की आड में यह न्यायालय इस सम्पूर्ण प्रकरण के गुणावगुण पर नये सिरे से सुनवाई कर निर्णय करने के पक्ष में नहीं है। माननीय एकलपीठ ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अध्ययन व पूर्ण विवेचन करने के पश्चात ही गुणावगुण</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>नजरसानी रेफ/टी.ए./80/2005/बीकानेर धर्मवीर सिंह बनाम सरकार</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>पर आलोच्य आदेश पारित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में यह सुस्थापित सिद्धान्त प्रतिपादित है कि नजरसानी एक अतिरिक्त रेफरेंस का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जाना संभव है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सी पी सी में प्रावधान दिये गये है। ए आई आर 1995 एस सी पेज 455, 2005 (1) आर आर टी 545 एस सी सहित न्यायिक दृष्टान्तों की एक श्रृंखला है, जिनमें यह अवधारित किया गया है कि नजरसानी का प्रावधान रेफरेंस अथवा अपील का स्थान नहीं ले सकता है। नजरसानी का दायरा अत्यधिक सीमित होता है और नजरसानी की आड़ में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। आर आर डी 2010 पेज 254 प्रेमराज बनाम श्रीमती मनभर देवी में राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-</p> <p><i>“(a) Hon’ble Supreme Court and the Hon’ble High Court have held in several matters that the remedy of review is not an instrument for re-examination of the facts and it cannot be utilized as an instrument for re-writing the judgment. The scope of review does not provide an opportunity of an extra appeal. It has been held that even when judgment is erroneous the scope of review is not attracted.</i></p> <p><i>(b) The scope of review is very limited and review is not the method of re-examination of a judgment. It even does not give any scope to the court to sit in appeal over the judgment pronounced by the same court. The scope permits only to correct the mistakes which are apparent on the face of the record. <b>Hon’ble Supreme Court in Smt. Meera Bhanja Vs. Nirmala Kumari Chaudhary, AIR 1995 SC page 455</b> clearly held that the error apparent on the face of the record should be such which should strike immediately looking at the face of the record and which does not require any long drawn process of reasoning or examination of law. The courts are not supposed to re-appreciate the evidence but only restrict themselves for correction of the mistakes which are visible on the face of the record. <b>In Ajit Kumar Rath Vs. Orissa State AIR 2000 SC 85, the Hon’ble Apex Court</b> has held that the power is not absolute and it is subject to restrictions indicated in Order 47 CPC. A review cannot be claimed as a remedy for a fresh hearing or for correction of an erroneous view taken earlier.</i></p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>नजरसानी रेफ/टी.ए./80/2005/बीकानेर धर्मवीर सिंह बनाम सरकार</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>(c) <i>The power of review can be exercised only for correction of error of law or fact which stares on the face without any elaborate argument being needed in establishing it. The error apparent on the face of the record is one which is self-evident and does not require a process of reasoning and it is distinct from erroneous decision. Rehearing the matter or detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the ambit of the jurisdiction of review. Jurisdiction of review cannot be used as an appellate jurisdiction in disguise. Hon'ble Supreme Court in State of Haryana Vs. Mohinder Singh 2003 (I) WLC (SC) page 499 considered the scope of review under Order 47 Rule 1 CPC which is reproduced here:- "Civil Procedure Code O.47 Rule 1- Scope- Hearing of review does not mean giving one more chance for rehearing matter already disposed of- High Court in hearing review as if it was rehearing whole petition overstepped its limits- Order of High Court set aside and original order restored."</i></p> <p>7. 2005(1) आर आर टी पेज 545 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-</p> <p><i>that even if a erroneous view taken on a particular issue, it cannot be a ground for review.</i></p> <p>8. इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 आरबीजे (12) पेज 290 में यह अभिनिर्धारित किया है कि-</p> <p><i>"The scope of review is very limited. It has been clearly held in a catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 47 Rule 1 CPC if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self-evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of the record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and can not be allowed to be an appeal in disguise."</i></p> <p>यहां तक कि यदि निर्णय में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी वह नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिव्यू पीटिशन संख्या 662/2001 बउनवान सुरेन्द्रकुमार वकील व अन्य बनाम चीफ एक्जीटिव आफिसर एम.पी. व</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>नजरसानी रेफ/टी.ए./80/2005/बीकानेर धर्मवीर सिंह बनाम सरकार</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रैल, 2004 में भी प्रतिपादित किया गया है, जो आरआरटी 2005 (1) पेज 545 पर उद्धरित है।</p> <p>9. प्रकरण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने एकलपीठ द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई जाहिरा त्रुटि "error apparent on the face of record" प्रकट नहीं कर पाये है जिससे इस नजरसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सकें। हमारी सुविचारित राय में प्रकरण की तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः पारित आदेश में नजरसानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है।</p> <p>10. परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति रेफरेंस पत्रावली में संलग्न की जावे।</p> <p>पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">( मदनलाल नेहरा ) सदस्य</p>	